मालदीव में एक बदलाव

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

26 सितम्बर, 2018

द हिन्दू

लेखक-
हर्ष वी. पंत (प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज, लंदन)

''भारत को इस क्षण को अपने पक्ष में करना होगा और द्विपक्षीय संबंधों का पुनर्निर्माण करना होगा।''

लोकतंत्र एक अजीब स्तर है। घरेलू राजनीति में यह उभर कर आने का एक तरीका है। यहां तक कि विदेशी संबंधों में, यह संकट को उसी तरह गायब कर सकता है जिस तरह इसने संकट का निर्माण किया था।

अधिकतर लोगों ने मालदीवियन चुनावों की नियंत्रित प्रकृति को देखते हुए माना था कि मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के लिए दूसरा कार्यकाल निश्चित है, लेकिन हिंद महासागर में छोटे द्वीपसमूह के लोगों ने परिवर्तन के लिए मतदान किया और विपक्षी उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को सत्ता में लाया। वे बड़ी संख्या में बाहर निकले और 89.2% मतदान के साथ श्री यमीन को निर्णायक झटका दिया।

डेमोक्रेटिक वोट-

चुनाव परिणाम के कुछ घंटों के बाद श्रीमान यमीन ने टेलीविजन के सहारे हार मानकर कहा कि 'मालदीव लोगों ने वही फैसला किया है जो वे चाहते थे। मैंने इस परिणाम को स्वीकार कर लिया है।'

श्री सोलिह मालदीव में एक वरिष्ठ राजनेता हैं और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी), जुमहोरे पार्टी और अधलाथ पार्टी के विपक्षी गठबंधन के लिए संयुक्त राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे।

उनकी जीत मालदीव के राजनेताओं की प्रतिबद्धता को उनके देश में लोकतंत्र के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। वर्ष 2012 में श्री यमीन द्वारा हटाए गए मालदीव के निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इस पर रेखांकित किया जब उन्होंने ट्वीट किया कि श्री सोलिह ने लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। यह लोकतंत्र के लिए डू और डाई के समान था और वे इसमें सफल भी हुए।

परिणाम निकलने के बाद, भारत के विदेश मामलों के मंत्रालय ने चुनाव के संदर्भ में कहा कि 'यह जीत न केवल मालदीव में लोकतांत्रिक ताकतों की जीत है, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों और कानून के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा श्री सोलिह, दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों के लिए अपने समर्थन को रेखांकित करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि मालदीव के लोगों ने 'अपने देश के भविष्य को निर्धारित करने के लिए अपनी लोकतांत्रिक आवाज उठाई है।'

मालदीव अपने पहले लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित नेता श्री नशीद के बाद से ही उथल-पुथल में रहा हैं, हांलाकि, इन्हें 2012 में पुलिस विद्रोह के बाद पद से हटा दिया गया था। इसके बाद 2013 में श्री यमीन के विवादास्पद चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम रद्द कर दिया।

श्री यमीन ने चीन और सऊदी अरब के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा दिया, भारत को अनदेखा कर दिया और 2016 में मालदीव को राष्ट्रमंडल से बाहर खींच लिया।

चीन की ओर झुकाव-

श्रीमान यमीन ने चीन का चुनाव किया और भारत को अपने से दूर रखा। पिछले साल चीन की यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) सहित 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए।

श्री यमीन ने न केवल चीन की महत्वाकांक्षी समुद्री सिल्क रोड पहल का समर्थन किया है, बल्कि चीन के साथ एफटीए में प्रवेश करने के लिए पाकिस्तान के बाद मालदीव को दक्षिण एशिया में दूसरा देश भी बनाया। यमीन सरकार ने विपक्षी सत्र में भाग लेने वाले विपक्ष के साथ, देश की संसद, मजलिस, चुपके से एफटीए को धक्का दिया।

विपक्षी ने यमीन सरकार पर आरोप लगाया कि मालदीवियन द्वीपों, प्रमुख बुनियादी ढांचे और यहां तक कि आवश्यक उपयोगिताओं के चीनी 'भूमि अधिग्रहण' की इजाजत देने का आरोप है, जो मालदीव की आजादी को कमजोर नहीं करता, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा को कम करता है।

चीनी ऋण द्वारा वित्त पोषित विशाल आधारभूत संरचना विकास श्री यमीन के चुनाव अभियान का एक प्रमुख हिस्सा था, लेकिन बड़े पैमाने पर ऋण जाल ने इसे स्वीकार करने के लिए एक कठिन प्रस्ताव बना दिया।

श्री यमीन ने हार मान ली हो लेकिन मालदीव को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

डेमोक्रेटिक संस्थानों को कमजोर कर दिया गया है और प्रभावी रूप से शासित नहीं होने पर एक नाजुक लोकतंत्र भी कट्टरपंथी विचारधाराओं के लिए अतिसंवेदनशील हो सकता है। और चीन जल्दबाजी में कहीं नहीं जा रहा है। मालदीव में इसकी आर्थिक उपस्थिति एक वास्तविकता है कि सभी सरकारों के साथ संघर्ष करना होगा।

मालदीव के नागरिकों द्वारा श्री यमीन के बहिष्कार ने निश्चित रूप से नई दिल्ली के लिए एक अनुकूल परिणाम तैयार किया है और इसलिए भारत को संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए इस पल को अपने पक्ष में करना चाहिए।

यदि मालदीव ने संकट से सबक सीख लिया है, तो भारत के पड़ोसी राजनीतिक अभिजात वर्ग आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर भारत पड़ोसी देशों के नागरिकों की आकांक्षाओं के साथ खड़ा होता है, तो दीर्घकालिक टिकाऊ रिश्ते की संभावनाएं काफी उज्ज्वल है।

* * *

GS World टीम...

भारत-मालदीव संबंध

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मालदीव में सोमवार को लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक उठापटक थम गई। मालदीव ने अपने नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया है।
- यहां विपक्षी उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोहिल ने निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन गयूम को हरा दिया।
- सोहिल की जीत के साथ ही भारत को बिगड़े संबंधों को सुधारने का एक बड़ा मौका मिल गया है। मालदीव में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह पलट गए हैं।
- चीन वहां अपना सामरिक विस्तार बहुत तेजी से कर रहा है। ऐसे में ये नतीजे चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं हैं।

मालदीव भारत के लिए क्यों है अहम?

- मालदीव हिंद महासागर में स्थित 1200 द्वीपों का देश है, जो भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम है।
- मालदीव के समुद्री रास्ते से निर्बाध रूप से चीन, जापान और भारत को एनर्जी की सप्लाई होती है।
- चीन 10 साल पहले से ही हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना के जहाजों को भेजना शुरू कर चुका था। अदन की खाड़ी में ऐंटी पायरेसी अभियानों के नाम पर मालदीव इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में धीरे-धीरे काफी अहम बन गया है।
- दक्षिण एशिया की मजबूत ताकत होने और हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के नाते भारत को मालदीव के साथ सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में मजबूत संबंध बनाए रखने की जरूरत है।
- मालदीव में चीन की बड़ी आर्थिक मौजूदगी भी भारत के लिए चिंता की बात है। कहा जाता है कि मालदीव को बाहरी मदद का 70 फीसदी हिस्सा अकेले चीन से मिलता है।
- कई लोगों का मानना है कि मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन कुछ वैसा ही कर रहे हैं जैसा श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने किया था। ऐसे में इस राजनीतिक संकट पर भारत की चौकन्नी नजर है।
- पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की एमडीपी समेत विपक्ष का समर्थन करने वाली मालदीव की बड़ी आबादी चाहती है कि भारत इस संकट में अपने पड़ोसी देश की मदद करे और यामीन के खिलाफ कार्रवाई करे।
- मालदीव SAARC का भी सदस्य है। ऐसे में इस इलाके में भारत को अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मालदीव को अपने साथ रखना जरूरी है। पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा उड़ी में किए गए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में होने वाले SAARC सम्मेलन का भारत द्वारा बहिष्कार करने के आह्वान पर मालदीव एकमात्र ऐसा देश था जिसने इस आह्वान पर अनिच्छा जताई थी।
- यामीन के शासनकाल में मालदीव में कट्टरपंथ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि सीरिया में लड़ाई के लिए मालदीव से कई लड़ाके गए थे। अपने पड़ोसी देश में कट्टरपंथ का बढ़ना भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
- मालदीव के साथ भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। मालदीव के साथ नई दिल्ली का धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंध है। 1965 में आजादी के बाद मालदीव को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में भारत शामिल था। बाद में भारत ने 1972 में मालदीव में अपना दूतावास भी खोला।
- मालदीव में करीब 25 हजार भारतीय रह रहे हैं। हर साल मालदीव जाने वाले विदेशी पर्यटकों में 6 फीसदी भारतीय होते हैं।
- मालदीव के लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार के लिहाज से भारत एक पसंदीदा देश है। विदेश मंत्रालय के अनुसार मालदीव के नागरिकों द्वारा उच्च शिक्षा और इलाज के लिए लॉन्ग टर्म वीजा की मांग बढ़ती जा रही है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. मालदीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मालदीव राष्ट्रमंडल में शामिल एक द्विपीय देश है।
2. मालदीव में मालदीव कांग्रेस के प्रत्याशी इब्राहिम सोलिह राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं।
3. इब्राहिम सोलिह द्वारा जुमहोरे पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल्ला यामीन को पराजित किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2 (b) 1 और 2
(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. मालदीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मालदीव व चीन के मध्य मुक्त व्यापार समझौता है।
2. मालदीव चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश है।
3. मालदीव ने समुद्री सिल्क रोड परियोजना को समर्थन दिया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 3
(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

3. निम्नलिखित में से किन पार्टियों का इब्राहिम सोलिह को सर्मथन प्राप्त है?

1. मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी
2. जुमहोरे पार्टी
3. अधलाथ पार्टी
4. मालदीव कांग्रेस

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें-

(a) 1 और 4 (b) 1, 3 और 4
(c) 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

1. Consider the following statements regarding Maldives-

1. Maldieves is a peninsular country included in Common Wealth.
2. Ibrahim Solih of Maldives Congress has been elected President of Maldives.
3. Ibrahim Solih defeated the Abdulla Yameen the condidate of Jamhoore Party.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 2 (b) 1 and 2
(c) 1 and 3 (d) All of the above

2. Consider the following statements regarding Maldives-

1. Free trade agreement is between Maldieves and China.
2. Maldives is the first country of South Asia to support free trade agreement with China.
3. Maldives has supported maritime Silk Road Project.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) 1 and 3
(c) Only 3 (d) All of the above

3. Which of the following parties have Supported Ibrahim Solih?

1. Maldivian Democratic Party
2. Jamhoore Party
3. Adhaalath Party
4. Maldive Congress

Choose the correct answer using the code given below-

(a) 1 and 4 (b) 1, 3 and 4
(c) 1, 2 and 3 (d) All of the above

नोट :

25 सितम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(c), 3(c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. भारत को पड़ोसी देशों से दीर्घकालिक टिकाऊ रिश्ते हेतु पड़ोसी अभिजात वर्ग नहीं वरन् पड़ोसी देशों के नागरिकों के आकांक्षाओं के साथ खड़ा होना है। आप इस तर्क से कहाँ तक सहमत है? (250 शब्द)

India does not need to be an autocratic neighbour but needs to stand with the ambitions of the citizens of neighbour countries for the longterm strong relation with neighbour countries. To what extent do you agree with this reasoning? (250 Words)

2. ''लोकतंत्र विदेशी संबंधों में संकटों को उसी तरह समाप्त कर सकता है, जिस तरह इसने संकट का निर्माण किया।'' उपरोक्त कथन के आलोक में भारत-मालदीव संबंधों की चर्चा करें। (250 शब्द)

"Democracy can resolve the problems in foreign relations in same way in which it has created it." In the reference to the above statement, discuss India-Maldive relations. (250 Words)